झिलमिल कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की मरम्मत

1058. **श्री हमाराम शाक्य :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा झिलमिल कालोनी और विवेक विहार में आवंटित क्वार्टरों की दीवारों और छतों की अब तक मरम्मत नहीं हुई है,

(ख) क्या वर्षा ऋतु में क्वार्टरों की छतें चूने से क्वार्टरों के निवासियों को भारी कठिनाइयां हुई और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केवल कुछ क्वार्टरों की मरम्मत की और शेष क्वार्टरों की मरम्मत नहीं की, और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी में मल्यवान पत्र एवं सामग्री का माइक्रोफिल्म लिया जाना

1059. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या लन्दन स्थित "इण्डिया आफिस लाइब्रेरी" की पुस्तक संग्रहों, मूल्यवान पत्रों तथा अन्य सामग्री के माइक्रो-फिल्म किया गया है या किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र 'चन्द्र') : (क) जी हां। उनको माइक्रोफिल्म किया जा रहा है।

(ख) समय का बिल्कुल सही अनुमान लगाना तो सम्भव नहीं है, परन्तु इसमें काफी समय लगने की सम्भावना है।

Change in Master Plan in Delhi regarding land use

1060 SHRI S. G. MURUGAIYAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Standing Committee of the Delhi Corporation has urged the Government to change the provisions of the Master Plan regarding use of land so as to enable the Corporation to regularise unauthorised and unapproved colonies and the residential structures built therein upto June 30 this year; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) A copy (English version) of the Resolution passed by the Standing Committee is laid on the Table of the House [*Placed in Library See* No LT-1136/77) Government have already decided to regularise various unauthorised colonies subject to terms and conditions in letter dated 16th February, 1977 A copy of the letter is annexed

An Implementation Body, has been set up to regularise unauthorised colonies in accordance with the instructions and this will, in the process of implementation, suggest changes in land use, where required.